



अधिकतम : 27°C
न्यूनतम : 14°C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, बुधवार 25 मार्च 2026 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 207 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

चैत्र कृष्ण पक्ष 7 विक्रमी संवत् 2083

5 शबाल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



अब देश का पसंदीदा निवेश स्थल बना यूपी: योगी
पेज 2



शांत रहने से आपको साफ नजरिया मिलता है: गिल
खेल टाइम्स



शिक्षा का बजट घटाया, तो पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी
सम्पादकीय



तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बारिश
पेज 12

संक्षिप्त समाचार

यूको बैंक के दो अधिकारियों सहित चार को पांच साल की सजा
नई दिल्ली। अहमदाबाद की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में यूको बैंक के अधिकारियों सहित चार व्यक्तियों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही उन पर कुल 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पहले मामले में गांधीनगर के चिलोडा शाखा के यूको बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक मेदम भगवती प्रसाद और तत्कालीन सहायक प्रबंधक भास्कर रमेशचंद्र सोनी के साथ साबरकांठा के हेवन फाइव एंटरप्राइज के प्रोपराइटर जयेंद्र सिंह दह्याजी मकवाना को बैंक धोखाधड़ी के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास और कुल 1.33 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

आई एंड पैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आई-पैक के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी की बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता, तो आपका रुख क्या होता। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंबारिया की बेंच ने पूछा कि क्या इड्यूटी पर मौजूद ईडी अधिकारी अपने अधिकार खो देते हैं। कोर्ट ने बताया कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर भी याचिका दायर की है। राज्य की ओर से सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी के पास अन्य कानूनी विकल्प हैं, इसलिए वह आर्टिकल 32 के तहत याचिका नहीं दे सकती।

रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के बदले नियम
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग फ्लॉट बदलने के नियमों में बदलाव किया है। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को यात्रा से 72 घंटे पहले कैंसिल करता है, तो उसे लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस दौरान केवल एक तय फ्लॉट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। जबकि बाकी राशि रिफंड कर दी जाएगी। इससे समय पर टिकट कैंसिल करने वालों को राहत मिलेगी। अगर टिकट 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल की जाती है, तो रेलवे किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काटेगा और बाकी पैसा लौटाएगा।

एक साल में निपटाएं आतंकवाद विरोधी केस: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। आतंकवाद विरोधी मामलों में सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों से कहा कि वे विशेष एनआईए अदालतों के माध्यम से यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी मामलों के मुकदमों को एक साल के अंदर निपटाने का प्रयास करें।

देश में पहली बार इच्छामृत्यु: एम्स में हरीश राणा की मौत

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। गाजियाबाद के हरीश राणा का मंगलवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। हरीश राणा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मिली थी। 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद दिल्ली के एम्स में हरीश राणा का निधन हो गया।
हरीश राणा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (आईआरसीएच) में भर्ती थे। उन्हें उपशामक देखभाल वार्ड में रखा गया था। वे पिछले एक सप्ताह से बिना खाना और पानी की जीवित थे। यह प्रक्रिया छह दिनों से चल रही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एम्स ने डाक्टरों की एक कमेटी गठित की और उसे 14 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि, डाक्टर के अनुसार हरीश राणा के शरीर से पोषण देने वाली ट्यूब निकाली नहीं गई थी, बल्कि उस पर कैंप लगा दिया गया था। इसी तरह पानी देने वाली ट्यूब को भी कैंप लगाकर बंद कर दिया गया था। इस तरह से हरीश राणा को इच्छामृत्यु देने की प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हुई थी। वहीं इससे पहले हरीश राणा के माता-पिता की ओर से उनके अंगदान का निर्णय लेने के बाद डाक्टरों ने उनको जांच की। हरीश राणा की मृत्यु के बाद उनके अंगों से दूसरे लोगों को भी जीवन मिल सकेगा। बता दें कि हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े होकर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। साथ ही पूरी प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए थे। एम्स के डाक्टर पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सामान्य बनाने पर काम कर रहे थे। इच्छामृत्यु की दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हरीश राणा से मिलने की अनुमति बंद कर दी गई थी।



13 साल से कोमा में थे हरीश
वे पिछले एक सप्ताह से बिना खाना और पानी के सांसें ले रहे थे

ईसाई या इस्लाम अपनाने पर खत्म होगा एससी का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट केवल हिंदू, बौद्ध व सिख को ही अनुसूचित जाति का मिलेगा दर्जा

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंबारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सुनाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद पादरी बने चिंथाडा आनंद ने याचिका दायर की थी कि उन्हें अकाला रामिरेड्डी समेत कुछ लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। 1985 के सुसाई बनाम भारत सरकार से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है, तो उसे एससी दर्जा प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति की जरूरत होगी।
ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है, तो उसे एससी दर्जा प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति की जरूरत होगी। केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को सुप्रीम कोर्ट ने सविधान के साथ धोखा करार दिया। यह मामला विशाखापट्टनम जिले के अनाकाल्लो का है, जहां मूल रूप से एससी (माला समुदाय) के चिंथाडा ने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी बन गया।



दोबारा हिंदू धर्म में लौटने पर एससी का दर्जा प्राप्त करने को विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति की जरूरत होगी

हिंसा और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ईसीआई का मास्टर प्लान

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को 'अंतर-राज्यीय सीमा बैठक' आयोजित की। इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले उपचुनावों से पहले, समन्वय बढ़ाना, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और फेयर चुनाव सुनिश्चित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की।

ईरान से जंग जारी रही, तो गंभीर नतीजे होंगे: पीएम मोदी

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में कहा कि अमेरिका-इजरायल को ईरान से जंग जारी रही, तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि होमजुस्ट स्ट्रेट में हारें जहाज और भारतीय क्रूफर्स हूए हैं।
ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस-तेल, फिटिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। एक दिन पहले पीएम ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय में



आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा
हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री ने ट्रम्प से की बात, होमजुस्ट पर जताई चिंता
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से फोन पर बात कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। खास तौर पर होमजुस्ट स्ट्रेट को खुला रखने की जरूरत पर दोनों नेताओं ने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा। दोनों नेताओं ने माना कि होमजुस्ट स्ट्रेट का खुला रहना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इजरायल-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।
गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। राज्य सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करें। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एजेंट्स हटते हैं। जहां से शिकायतें आती हैं, वहां कार्रवाई की जाए। संकट कितना भी बढ़ा है, भारत की तेज गति बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।

लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानून में संशोधन करने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल के जरिये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सुरक्षा और उनके अधिकारों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है।
अब इस कानून के तहत उनकी पहचान, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को बेहतर रखा होगा। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने बिल को लेकर चर्चा की, लेकिन अंत में यह पारित हो गया। सरकार का कहना है कि यह कदम ट्रांसजेंडर लोगों को

लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव को झटका

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने दर्ज एक आईआर रह केंस को मांग की गई थी।
जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। दाखिल याचिका में कहा गया था कि सीबीआई ने यह केस बिना



दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से किया इन्कार
जरूरी सेशन के दर्ज किया गया, जो कानूनी रूप से अवैध है। मामले

गैस लेकर दो भारतीय जहाज 26 व 27 मार्च को पहुंचेंगे भारत

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने मंगलवार को दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल और गैस संकट पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा कि दो भारतीय एलपीजी जहाज- पाइन गैस और जग वसंत होमजुस्ट स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं।
राजेश सिन्हा ने बताया कि पाइन गैस करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 27 मार्च को न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा, जबकि जग वसंत लगभग 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 26 मार्च को कांडला पहुंचने वाला है। इन जहाजों के निकलने के बाद अब फारस की खाड़ी में 20 भारतीय जहाज हैं, जिन पर 540 भारतीय नाविक सवार हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि जंग के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन किसी भी डिस्टीयूबटर पर गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ पैनिक बुकिंग देखी गई, लेकिन डिलीवरी सामान्य रही। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई भी पर्याप्त है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी



दोनों भारतीय एलपीजी जहाज- पाइन गैस और जग वसंत होमजुस्ट स्ट्रेट पार कर चुके: केंद्र सरकार

कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंब्राबी को उम्रकैद

श्रीनगर। कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंब्राबी को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए आतंकी वित्तपोषण और साजिश के मामले में सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत अंब्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर कई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यूएपीए की धारा 18 के तहत अंब्राबी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त अर्धी को सजा सुनाई गई। सह-आरोपी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरिन को अमानवीय दंड संहिता (यूएपीए) की धारा 18 के तहत 30 वर्ष के साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों को यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत जुर्माने के साथ-साथ 10-10 साल की साधारण कैद की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत चार-चार वर्ष की सजा भी सुनाई गई।
साथ-साथ पांच-पांच साल की सजा भी सुनाई। आईपीसी की धारा 121ए के तहत, उसे आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त अर्धी को सजा सुनाई गई। सह-आरोपी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरिन को अमानवीय दंड संहिता (यूएपीए) की धारा 18 के तहत 30 वर्ष के साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों को यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत जुर्माने के साथ-साथ 10-10 साल की साधारण कैद की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत चार-चार वर्ष की सजा भी सुनाई गई।



सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरिन को 30 साल की जेल

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

कैसे रुकेगा युद्ध

मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। 24 दिन गुजर जाने के बावजूद इस युद्ध में कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। हां थोड़ी आशा उस समय जरूर बंधी थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने 48 घंटों के अल्टीमेटम के बाद ईरान पर हमला करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर उसको पांच दिन के लिए टाल दिया था। ट्रम्प ने दावा किया था कि ऐसा वह इसलिए कर रहे हैं ताकि पेट्रोल के पीछे चल रही ईरान से बातचीत किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचे। उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। ट्रम्प के इस फैसले के तुरंत बाद ईरान की तरफ से जवाब आया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है और बातचीत अगर कोई होगी भी तो वह ईरान की शर्तों पर होगी। जिस तरह दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए, उससे भी पांच दिन के संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस्मैल के तेल अवीव सहित कई शहरों पर मिसाइल से हमले किए, तो वहीं इस्मैल अमेरिका ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की। हालांकि ट्रम्प अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन ऐसा कहते हुए वह यह कहने से भी नहीं चूके कि ईरान अमेरिका की शर्तों के अनुसार ही चलेगा और वह ईरान को न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बनने देंगे। साथ ही उनका दावा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को भारी क्षति पहुंचाई है और उसकी सेना लड़ने की स्थिति में नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत उससे अलग ही दिखाई दे रही है। जहां तक बात भारत की है, भारत भी यही चाहता है कि किसी भी तरह यह युद्ध रुके। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में ट्रम्प ने टेलीफोन पर बात भी की। इस बातचीत में कहा जा रहा है कि होर्मुज स्टेट को खोलने से लेकर अन्य तमाम बातों पर बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिखाई दी। इसमें कोई दोराय नहीं कि हर कोई चाहता है कि यह युद्ध रुके। उसका कारण भी है, भले ही यह युद्ध ईरान-अमेरिका/इस्मैल के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल, गैस का संकट लगभग प्रत्येक देश के सामने खड़े हो गया है, क्योंकि जिस तरह दोनों की ओर से एक-दूसरे के ऊर्जा संसाधनों पर हमले किए जा रहे हैं, वह सभी के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। जाहिर है हर देश का नेतृत्व इस समय चिंतित दशा में है और नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में यह युद्ध आगे बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे तो लगता है कि वह युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका सहयोगी देश इस्मैल उनसे सहमत होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब पांच दिन के संघर्ष विराम की घोषणा ट्रम्प ने की थी, तब भी इस्मैली प्रधानमंत्री नेत्याहू ने इस पर ठंडी प्रतिक्रिया दी थी। अभी भी विश्व के बड़े नेता अपनी जिम्मेदारी को समझें, ताकि विनाश को रोका जा सके।

अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं पीएम

पूर्व निर्धारित करल दौरे के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकूंगा, इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, लेकिन सरकार पहले ही गंभीर गलती कर चुकी है, व्यवस्था का ढांचा ही कमजोर कर दिया गया है, जिस सुधारने में काफी समय लगेगा, पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय अमेरिका और इस्मैल के प्रभाव में काम करते हैं और किसानों व युवाओं के हित में प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहे हैं।



-राहुल गांधी, नेता विपक्ष

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) समाप्त हो चुका था, ब्रिटेन जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। ब्रिटिश संसद चल रही थी और उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लिमेंट एटली। बजट पर बहस जारी थी। तमाम ब्रिटिश सांसदों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली से कहा आपने रक्षा से लेकर तमाम मर्दानों में बजट में जबरदस्त कटौती कर दी है, लेकिन शिक्षा के बजट में कटौती क्यों नहीं की? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने मुस्कुराते हुए कहा-हम युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई तो कर लेंगे, लेकिन अगर बजट के अभाव में हमारी पीढ़ियों की शिक्षा प्रभावित हुई तो इसका नुकसान कोई नहीं भर पाएगा। यह कह कर उन्होंने शिक्षा के बजट में कटौती करने से साफ मना कर दिया। ब्रिटेन में वर्ष, 1944 के बटलर शिक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने पर जोर दिया गया, जिससे ब्रिटेन में शिक्षा का महत्व बना रहा।

यह सुखद आश्चर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इंग्लैंड में वर्ष, 1944 में ऐतिहासिक शिक्षा सुधार पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा वित्तपोषित शिक्षा के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। एक ओर युद्ध चला रहा हो और दूसरी ओर ब्रिटेन अपनी शिक्षा, अपने स्कूलों, कालेजों को उन्नत बनाने के प्रयास कर रहा था, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। तत्कालीन सरकार ने अपनी कल्याणकारी राज्य की सोच को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बाद ब्रिटेन में नई शिक्षा प्रणालियां विकसित हुईं। एटली सरकार ने 1944 के जिस शिक्षा अधिनियम को लागू किया, उसे शबटलर एक्ट कहा जाता है, जिसने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए। एटली ने कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाई।

इंग्लैंड में आरंभ से ही शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और न्यू इनोवेशन ही वह मूल था जिसने वर्ष, 1760 से वर्ष, 1840 के बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ की। हस्तशिल्प का सफर मशीनों तक आया। भाप के इंजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोयला औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार बन कर निकला और लोहा उद्योग से लेकर कपड़ा उद्योग एक नई इबारत लिखने लगा। कारखाने लगे तो शहरीकरण हुआ और फिर सब कुछ तेजी से बदलना आरंभ हुआ। विश्वयुद्ध हो या महामारी, वैश्विक आर्थिक स्थिति नकारात्मकता में हो या कोई अन्य कारण

शिक्षा का बजट घटाया, तो पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी



इंग्लैंड ने उसकी आंच कभी भी अपने कालेजों व विश्वविद्यालयों पर नहीं आने दी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वर्ष, 1096 में स्थापित हुआ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वर्ष, 1209 में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वर्ष, 1826 में, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय वर्ष, 1824 में, किंग्स कॉलेज लंदन वर्ष, 1829 में, इंपीरियल कॉलेज लंदन वर्ष, 1907 में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वर्ष, 1895 में स्थापित हुआ। जबकि दरहम विश्वविद्यालय वर्ष, 1832 में, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय वर्ष, 1876 में और वारविक विश्वविद्यालय वर्ष 1965 में स्थापित हुए। इनकी वित्तीय कटौती किसी भी सूरत में कभी नहीं की गई।

उधर चीन ने शिक्षा, तकनीक, न्यू इनोवेशन के महत्व को समझा और उस पर कभी कोई समझौता नहीं किया। इस बीच चीन के थिंक टैंक ने लगातार इंग्लैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों में हुई प्रगति पर नजर बनाए रखी और उसने भी शिक्षा और अनुसंधान को अपना हथियार बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद से ही चीन ने कमर कसी और उसने वर्ष, 1949 में 20 से 40 प्रतिशत की रफ्तार से साक्षरता दर हासिल की और वर्ष 2000 आते-आते चीन की करीब 98.4 प्रतिशत की आबादी शैक्षिक रूप से समृद्ध हो चुकी थी। इसके साथ ही चीन ने शिक्षा और अनुसंधान यानी R-D में जो छलांग लगाई है,

वह दूसरे देशों के लिए एक सीख है। यह R-D के क्षेत्र को अभूतपूर्व क्रांति है। इसने देखते ही देखते विगत 30 सालों में चीन को तकनीकी महाशक्ति बना दिया। चीन ने वर्ष, 1986 में अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया और वर्ष, 1999 के बाद R-D में भारी निवेश किया। यह निवेश वर्ष, 2011 में +100 बिलियन डॉलर से अधिक का था। आज चीन 3,000 विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक, बौद्धिक, तकनीक, साइंस आदि क्षेत्रों में हर बार कोई न कोई नई खोज सामने रख कर आश्चर्यचकित कर देता है। R-D यानी अनुसंधान और विकास में चीन ने सालाना 20 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, जिसने चीन को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक में अग्रणी बना दिया। इसके अलावा चीन ने अपने विश्वविद्यालयों का जबरदस्त आधुनिकीकरण किया और 147 विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए विशेष फंड और संसाधन झोंक दिए। आज चीन ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग व स्मार्ट क्लासरूम में दुनिया में सबसे आगे है, जो AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी माडल की कार्पा की और विश्व भर की विदेशी प्रतिभाओं को चीन आमंत्रित किया। चीन लगातार विदेशी छात्रों को सहायता को बढ़ा रहा है। यह संख्या 2024 तक करीब 5 लाख तक पहुंच चुकी है। इससे उलट हमारे देश में सबसे बुरी गत शिक्षा, अनुसंधान

पवन सिंह



और न्यू इनोवेशन को लेकर हुई। इसे बढ़ाने की बजाए इसे गत में झोंक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि मैनुफैक्चरिंग ग्रांथ चरमरा गई और धीरे-धीरे हम तकनीकी मामले में चीन पर निर्भर होते चले गए। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, चीन से भारत में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (लगभग 47.67 अरब डॉलर) और मशीनरी, परमाणु रिएक्टर व बॉयलर (लगभग 27 अरब डॉलर) का सबसे अधिक आयात किया गया। ये दोनों श्रेणियां मिलकर 70 अरब डॉलर से अधिक की हैं। वर्ष, 2024-25 में चीन से भारत को प्रमुख मशीनरी आयात में विद्युत-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण- 38 अरब डॉलर से 47 अरब डॉलर से अधिक और परमाणु रिएक्टर और बॉयलर मशीनरी-21.7 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर के अलावा अन्य तकनीकी उपकरण (ऑप्टिकल, मेडिकल)- 2.56 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर रहा। चीन शिक्षा और अनुसंधान R-D में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। 2026 में, चीन ने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी बजट को बढ़ाकर 426.4 बिलियन युआन (लगभग +59-60 बिलियन) कर दिया है, जो 2025 से 10 प्रतिशत अधिक है। समग्र शिक्षा बजट 800 बिलियन डॉलर से अधिक का है, जो उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा और तकनीकी विकास पर भारी फोकस दर्शाता है। मुझे यह लिखने में कोई गुरेज नहीं है कि आज मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मामले में हम चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि हमने अपने देश में कभी भी साइंटिफिक एप्टीट्यूट या साइंटिफिक टेपरामेंट डेवलप होने ही नहीं दिया। शिक्षा और अनुसंधान हमारे लिए कभी प्राथमिकता में रहा ही नहीं। हमारे पास तथाकथित कामों के लिए तो करोड़ों रुपये होते हैं, लेकिन स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए, रिसर्च के लिए बजट न के बराबर होता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

27 मार्च को नेपाल में सत्तारूढ़ होगी बालेन सरकार

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जन्म अभी पिछले चुनाव में ही हुआ है। पहली मर्तबा चुनाव में उतरी इस पार्टी को 20 सीटें हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव में इस पार्टी की सुनामी थी जिसमें पुरानी पार्टियों के सारे धुरंधर धराशाई हो गए। देखा जाए तो नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वथा पहली बार किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बालेन सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर नेपाल के पड़ोसी देशों में भी उत्सुकता देखी जा रही है। अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से बिल्कुल ही अपरिपक्व बालेन सरकार नेपाल के लिए क्या कुछ कर पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।



यशोदा श्रीवास्तव

नेपाल में 27 मार्च को गठन होने जा रही नई सरकार को लेकर नेपाली जनता में उत्सुकता का माहौल है। इसी के साथ हर वर्ग में आशा और विश्वास भी है। चारों ओर चर्चा है कि अब नेपाल को परिवर्तन की अनुभूति होगी। मायूसी और निराशा के बादल छटेंगे। अबकी बार बालेन सरकार का नारा हर ओर गुंजायमान है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराएंगे। काठमांडू में जगह जगह बालेन शाह, रवि लामा छाने और सुदान गुरूंग के पोस्टर लगाए गए हैं। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नई सरकार को सत्ता सौंपने की तैयारी में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के शपथ से पहले 26 मार्च को सभी सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। गौरतलब है कि नेपाल करीब चार सौ सालों तक राजशाही के अधीन था। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का जनक माना जाता है। राजशाही से मुक्ति के लिए राजनीतिक दलों ने यदा कदा आंदोलन जरूर चलाया, लेकिन इसमें कामयाबी 2008

में जनयुद्ध नाम से चले हिंसक आंदोलन के बाद मिली। माओइस्ट नेता प्रचंड और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में सालों साल चले इस आंदोलन में करीब पांच हजार लोग मारे गए। राजा समर्थक राजनेताओं और जमिन्दारों के घर जलाए गए उनकी हत्याएं की गईं। इस भारी खून खराबा से घबड़ाए तत्कालीन नरेश ज्ञानेंद्र ने सत्ता त्यागने की घोषणा की। कहना न होगा नेपाल को लोकतंत्र के सूर्योदय के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।

2008 में हुए संविधान सभा के चुनाव में अपूर्ण बहुमत के बावजूद प्रचंड प्रधानमंत्री बने लेकिन नौ माह बाद ही उन्हें सत्ता छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद 2026 में संपन्न हुए चुनाव तक नेपाल को अस्थिर और गठबंधन सरकार का बोझ ढोने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान करीब 13 प्रधानमंत्री आए गए लेकिन नेपाल जिस का तस रहा। भ्रष्टाचार इस स्तर तक चरम पर पहुंच गया कि सत्ता और विपक्ष के शीर्ष नेताओं तक के हाथ इसमें सने हुए मिले। नेपाली जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। भ्रष्ट सरकारों की श्रृंखला में के पी शर्मा ओली अंतिम प्रधानमंत्री साबित हुए जिसे दुनिया ने देख कि किस तरह जेन जी आंदोलनकारियों ने भारी अपमान के बीच सत्ता छोड़ने को मजबूर किया। इसके अलावा अन्य दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी किस कदर खेत खेत भागकर अपनी जान बचा पाए, यह भी दुनिया में देखा। किसी सरकार के प्रति जनता जब गुस्सा करती है तो उसका क्या हथ्र होता है, नेपाली जनता ने यह कर दिखाया। बहरहाल उसके बाद नेपाल में अंतरिम

सरकार का गठन हुआ फिर छह महीने बाद चुनाव हुआ और इस चुनाव में सर्वथा पहली बार नेपाल को पूर्ण बहुमत की सरकार नसीब हुई। दरअसल नेपाली जनता को राजशाही से असल मुक्ति अब महसूस हुई, लेकिन अनुभूति होना अभी बाकी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी जिस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होने जा रही है, उससे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है। इस उम्मीद पर खरा उतरना यद्यपि कि आसान नहीं है, लेकिन नई सरकार यदि पचास प्रतिशत ही जनता की अपेक्षा पर खरा उतर पाई तो यह बड़ी कामयाबी होगी। नई सरकार का मुखिया बालेन शाह का ही बनना तय है। इस पद को लेकर चल रही कयासबाजी और शंका आशंका सब निर्मूल है। बालेन मंत्रिमंडल में फिलहाल उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामा छाने होंगे। जेन जी आंदोलन के नायक सुदान गुरूंग का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तराई जां सरकार में अहम भागीदारी से अछूता रह जाता रहा, यहाँ से भी कम से कम चार मंत्री होंगे। काफ़ी संभावना है भारत सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले से सांसद चुने जाने पर विशेष अधिकारी विक्रम सिंह थापा को बालेन शाह सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। विक्रम सिंह थापा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से सांसद चुने गए हैं। बालेन मंत्रिमंडल में क्षेत्र और जाति संतुलन पर विशेष ध्यान होगा। बालेन मंत्रिमंडल में अपेक्षाकृत युवा चेहरे भी होंगे। इसे लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

गणेश शंकर विद्यार्थी : वह शहादत जिसने पत्रकारिता को अमर कर दिया

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महासमर में जहां एक ओर तलवारों की खनक और बंदूकों की गूँज थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी वैचारिक क्रांति की धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसने जनमानस के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। इस वैचारिक क्रांति के पुरोधाओं में एक ऐसा नाम दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकता है, जिसने अपनी लेखनी को ही अपना अस्त्र बनाया और सत्य की बलिबेदी पर स्वयं को न्योछावर कर दिया। वह नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, जो एक संस्था, एक विचार और निष्ठीक पत्रकारिता के जीवंत प्रतिमान थे। उनका व्यक्तित्व उस पारस पत्थर के समान था, जिसके स्पर्श से सामान्यजन भी राष्ट्रभक्त के स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते थे। उनकी जीवन यात्रा उस शरारत संघर्ष की गाथा है, जहां एक अकेला व्यक्ति अपनी नैतिक शक्ति के बल पर साम्राज्यवादी सत्ता को चुल्लू हिलाने का साहस रखता था। इलाहाबाद की पावन धरा पर 26 अक्टूबर 1890 को अंतरसुइया के एक साधारण कायस्थ परिवार में जब इस बालक का जन्म हुआ तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह शिशु भविष्य में भारतीय पत्रकारिता का सूर्य बनेगा। पिता जयनारायण, जो स्वयं एक शिक्षक थे, ने गणेश को अनुशासन और ज्ञान की वह घुट्टी पिलाई, जिसने उनके भीतर सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का बीजारोपण किया। यद्यपि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और अंग्रेजी के वातावरण में हुई किंतु उनका भीतर भारतीयता का जो ज्वार उमड़ रहा था, उसने उन्हें हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चिंतन की ओर मोड़ दिया। उनके



श्वेता गोयल

भीतर की तड़प केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी बल्कि वे समाज की विसंगतियों और पराधीनता की बेड़ियों को देख रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने नाम के साथ 'विद्यार्थी' शब्द जोड़ा, जो इस बात का प्रतीक था कि वे जीवन के अंतिम क्षण तक एक जिज्ञासु और सीखने वाले साधक बने रहेंगे।

उनकी पत्रकारिता का अध्याय तब प्रारंभ हुआ, जब देश में स्वाधीनता की चेतना अंगड़ाइयां ले रही थी। 'कर्मयोगी' में पंडित सुंदरलाल के सान्त्विक पत्रों ने उन्होंने शब्दों की शक्ति को पहचाना। बाद में जब उन्हें 'पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी' जैसी महान विभूति ने 'सरस्वती' के संपादन का प्रस्ताव दिया तो यह किसी भी युवा लेखक के लिए एक महान उपलब्धि हो सकती थी किंतु विद्यार्थी जी का लक्ष्य केवल साहित्यिक परिष्कार नहीं था, वे तो उन शोषितों की आवाज बनना चाहते थे, जिनकी पुकार सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने 'सरस्वती' के वैभव के स्थान पर 'अभ्युदय' के संघर्षपूर्ण मार्ग को चुना। उनका मानना था कि शिक्षा, रिता केवल अक्षरों का विन्यास नहीं है बल्कि यह वह मशाल है, जो अंधेरे को चीरने का सामर्थ्य रखती है।



9 नवम्बर 1913 का दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की भांति अंकित है, जब कानपुर की तंग गलियों से 'प्रताप' का उदय हुआ। यह केवल एक साप्ताहिक पत्र नहीं था बल्कि फिरींगियों के विरुद्ध एक युद्धघोष था। 'प्रताप' के माध्यम से विद्यार्थी जी ने वह कर दिखाया, जो बड़ी-बड़ी सेनाएं नहीं कर पाती थी। उन्होंने किसानों की पीड़ा, मजदूरों का शोषण और रियासतों के अत्याचारों को अपनी स्याही से ऐसा उकेरा कि अंग्रेज सरकार के पसीने छूटने लगे। उनकी लेखनी में वह धार थी, जो सीधे जनमानस के हृदय को बेधती थी। उन्होंने

पत्रकारिता को दरबारी संस्कृति से निकालकर गलियों और खेतों तक पहुंचाया। उनके लिए निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होकर अन्याय से लोहा लेना था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए विद्यार्थी जी एक कांटा बन चुके थे। उन पर अनगिनत मुकदमे चले, भारी जुर्माने लगाया गया और बार-बार कारावास की कालकोठरी में धकेला गया। पांच बार जेल जाने के बाद भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी बल्कि वे हर बार और अधिक तपकर कुंदन की तरह बाहर निकले। जेल की यातनाएं उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकीं। उन्होंने जेल में रहकर 'जेल जीवन की झलक' जैसी कृतियां रची, जिन्होंने जेल की चारदीवारी के भीतर के सच को दुनिया के सामने रखा। उनकी लेखनी ने स्वाधीनता सेनानियों के भीतर वह ऊर्जा भरी कि 'प्रताप' का कार्यालय क्रांतिकारियों का तीर्थस्थल बन गया। विद्यार्थी जी का राजनीतिक जीवन भी उनके पत्रकारिता के समान ही ओजस्वी था। वे केवल लिखने वाले बौद्धिक नहीं थे बल्कि कर्म के पथ पर चलने वाले योद्धा थे। उनके लिए पद कभी साध्य नहीं रहे, केवल साधन रहे। उनके भीतर एक अद्भुत समन्वय था, वे एक ओर अहिंसा के पुजारी थे तो दूसरी ओर अन्याय के विरुद्ध किसी भी हद तक जाने वाले बागी। गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन का जो पक्ष उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करता है, वह है उनकी सांप्रदायिक सर्वभाव के प्रति अटूट आस्था। वे भली-भांति समझते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर टिकी है। उन्होंने अपने लेखों में बार-बार चेतावनी दी कि धर्म का राजनीतिक उपयोग

समाज के लिए विष के समान है। वे अक्सर कहा करते थे कि धर्म का स्थान मनुष्य का हृदय है, सड़क या संसद नहीं। मार्च 1931 का वह काल समय आया, जिसने भारत माता के इस सपुत्र को हीन किया। पूरा देश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के शोक में डूबा हुआ था। कानपुर में सांप्रदायिक दंगों की भयावह आग भड़क उठी थी। चारों ओर उन्माद का तांडव था, मानवता कराह रही थी और भाई-भाई का खून बहा रहा था। ऐसे समय में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबकते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी नंगे पैर, निहत्थे उस दहकती हुई आग के बीच कूद पड़े। उनके मित्रों और परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि यदि मेरा जीवन भाईयों को बचाने में काम आए तो इससे बड़ी सार्थकता और क्या होगी? वे गलियों में घूम-घूम कर दंगाइयों को समझाते रहे, असहाय महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते रहे। 25 मार्च 1931 को उस उन्मत्त भीड़ ने, जिसके भीतर से विवेक लुप्त हो चुका था, इस शांतिदूत पर प्रहार किया। विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति ने उम्रभर गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, वही उसी भीड़ की नफरत का शिकार हो गया। उनकी शहादत ने देश को स्तब्ध कर दिया। विद्यार्थी जी का बलिदान केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था बल्कि वह घृणा के विरुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा थी। आज के इस दौर में, जब सूचनाओं के महासागर में सत्य कहीं खो गया है और पत्रकारिता के आदर्शों पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



उत्तरी इजरायल। किरयात शमोनान में लेबनान से इजरायल की ओर रॉकेट दागे जाने की चेतावनी के बाद हवाई हमले के सायरन बजने पर छिपते इजरायली सुरक्षा जवान।

ईरान: मोहम्मद बागेर जोल्हाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख नियुक्त
 तेहरान। ईरान सरकार ने मोहम्मद बागेर जोल्हाद को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव नियुक्त किया है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'ईरना' ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी। जोल्हाद इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहे अली लारीजानी का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि अली लारीजानी इजरायल के एक हमले में मारे गए थे। उसके बाद से यह पद रिक्त था। जोल्हाद को नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ईरान की वह शीर्ष संस्था है जो देश की रक्षा और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता का मार्गदर्शन करती है।

संक्षिप्त समाचार

वियतनाम में एक भोजनालय में आग लगने से दो की मौत
 हनोई। दक्षिणी वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में सोमवार रात एक शाकाहारी भोजनालय में आग लगने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। वियतनाम न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो पीड़ित सो रहे थे। स्थानीय दैनिक वीएन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पड़ोसी ने बताया कि घटना के समय भोजनालय बंद था।

कोलंबिया में सैन्य विमान दुर्घटना में 66 सैनिकों की मौत
 बोगोटा। कोलंबिया के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत पुटुमायो में सोमवार को हुए एक सैन्य विमान दुर्घटना में 66 सैनिकों की मौत हो गई। कोलंबिया की सेना ने कहा नए आर्कडों के मुताबिक विमान में 128 लोग सवार थे, जिनमें से 57 घायल हो गए, चार लापता हैं और एक व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेना ने शुरू में कहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए परिवहन विमान सी-130 हर्क्यूलस में 114 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे। इस विमान का इस्तेमाल सैनिकों को लाने-ले जाने के लिए किया जाता था।

टोंगा तट के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप: भूकंप विज्ञानी
 मॉस्को। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएसएसी) ने मंगलवार को बताया कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश टोंगा के तट के दक्षिण-पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंपितशाली भूकंप आया है। शक्ति विज्ञानियों के अनुसार, यह भूकंप 04:37 जोएएमटी पर आया, जो शहर नेडफू से लगभग 158 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था। इसका केंद्र 218 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। फिलहाल इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या हावाहवात होने की कोई सूचना नहीं है।

कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश, 66 की मौत

114 कोलंबियाई सैनिक और 11 कू मेंबर सवार थे, टेकऑफ के बाद 1.5 किमी दूर गिरा

बोगोटा। कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स का हर्क्यूलस सी-130 विमान टेक-ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में अब तक 66 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। जबकि 4 सैनिक अभी भी लापता हैं। एक सैन्य सूत्र ने एएफपी को बताया कि 58 सैनिक, छह वायुसेना कर्मी और दो पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। यह हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूटो लेगुइजामो में हुआ। रक्षा मंत्री पेद्रो सां. चेज ने बताया कि विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। विमान में 114 सैनिक और 11 कू मेंबर सवार थे। कोलंबिया की सेना ने बताया कि इस हादसे में करीब 80 सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने सैन्य विमान हादसे पर दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर हादसा है।



ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और जवानों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सरकार सेना को मजबूत बनाने और बेहतर सुविधाएं देने पर काम कर रही है, ताकि आगे ऐसे हादसे न हों। पेद्रो ने कहा कि सेना के हथियार और संसाधनों को आधुनिक बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नागरिक या सैन्य अधिकारी इस चुनौती के अनुकूल काम नहीं कर पाए, तो उन्हें हटाया जाएगा।

रूस ईरान को खुफिया जानकारी साझा कर रहा है: जेलेस्की

कीवा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की ने कहा है कि उनके पास 'पुख्ता सबूत' हैं कि रूस ईरान को खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। यह दावा यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी (एचयूआर) के प्रमुख ओलेह इवाशचेंको के साथ बैठक के बाद किया गया, जिसमें जेलेस्की ने प्रस्तुत मूल्यांकन की समीक्षा की। जेलेस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट में चर्चा का सार देते हुए कहा कि रूस अपनी रडियो-तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया क्षमताओं का उपयोग कर रहा है, साथ ही मध्य पूर्व के भागीदारों से प्राप्त कुछ खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है। इन आरोपों पर रूस या ईरान की ओर से अभी कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेलेस्की का बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है।

परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था: किम जोंग

प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं, कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था।



2019 में ट्रम्प के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सबसे सही कदम था

किम ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने यह बयान सोमवार को संसद में लंबे भाषण के दौरान दिया। अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया और कहा कि वह अपने देश की परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे, ताकि अमेरिका को रोका जा सके। किम जोंग उन का यह भाषण मंगलवार को लिखित रूप में जारी हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि 2019 में ट्रम्प के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सबसे सही कदम था। किम ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चे में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा। हालांकि उन्होंने ट्रम्प का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि उनके विरोधी टकराव चाहते हैं या शांति, यह उन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया हर विधि के लिए तैयार

है। किम ने देश को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने, ज्यादा परमाणु हथियार और उच्च ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर जोर दिया। किम ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों की वजह से नॉर्थ कोरिया अब ज्यादा सुरक्षित है और इसी वजह से वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए भी कर पा रहा है। साउथ कोरिया को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसे सबसे बड़ा दुश्मन मानेंगे और पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे। अगर साउथ कोरिया कोई भी

कदम उठाता है जो उनके देश को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कई दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश, प्रतिबंध और बातचीत के जरिए नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए मंजूराने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब तक सभी प्रयास असफल रहे हैं। व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद ट्रम्प ने किम से फिर बातचीत करने की इच्छा जताई है। हालांकि, किम का कहना है कि बातचीत तभी हो सकती है, जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दे। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से यह कहता रहा है कि अगर लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इरान के सदा姆 हुसेन के पास परमाणु हथियार होते तो उनका अंत इस तरह नहीं होता।

तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की बारिश

विरोधभासी बयानों ने पश्चिम एशिया संकट को और जटिल बना दिया



तेल अवीव सहित कई स्थानों पर हमलों के प्रभाव देखे गए इमारतों को भारी नुकसान

तेल अवीव/वाशिंगटन। ईरान ने मंगलवार तड़के तेल अवीव सहित मध्य इजरायल पर मिसाइलों की कई लहरें दागीं, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच संभावित वार्ता को लेकर विरोधभासी बयानों ने पश्चिम एशिया संकट को और जटिल बना दिया है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, आधी रात के बाद 10 घंटे से भी कम समय में ईरान ने सात चरणों में मिसाइल हमले किए। तेल अवीव सहित कई स्थानों पर हमलों के प्रभाव देखे गए, जहां इमारतों को नुकसान, जलते वाहन और घना धुआं देखा गया।

आपातकालीन टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं। डिमोना क्षेत्र में भी एयर रेड सायरन बजाए गए, जो नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के निकट स्थित है, जिससे हमलों के दायरे के विस्तार का संकेत मिला है। इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने बताया कि कई स्थानों पर खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया और रातभर मिसाइल हमले जारी रहे। इसके साथ ही इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए ईरान में 50 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट और सैन्य अवसंरचना शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 3000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर ट्रंप ने दावा किया कि सप्ताहांत में हुई बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 'महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति' बनी है और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर प्रस्तावित हमलों को पांच दिन के

ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला

तेल अवीव/तेहरान/वाशिंगटन। अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का आज 25वां दिन है। ईरान में मंगलवार को कई जगह एनजीई-इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कनेक्शन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खोरमशहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। वहीं लेबनान में ईरान समर्थक उपग्रहीक संगठन हिजबुल्लाह ने आज इजरायल के 5 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने इजरायली सैनिकों की एक छावनी, रेडार लिए टाल दिया गया है। उन्होंने '15 बिंदुओं पर सहमति' की बात भी कही और तनाव कम होने के संकेत दिए। ईरान ने कुछ ही समय में ईरानियों को कोमलता में कुछ नरमी कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ 'कोई वार्ता' नहीं हुई है, जिससे संभावित समझौते को

अमेरिका-इजरायल के अलावा अन्य देशों के जहाजों को निकलने का रास्ता दिया जाएगा: पेजेशकियान

तेहरान। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को होर्मुज्ज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पेज. शकियान ने सोमवार को पार्किस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई फोन वार्ता में कहा कि किसी भी सुरत में, ईरान ने इस जलमार्ग से जहाजों के पार होने के लिए सुरक्षा जलमार्ग के इंजाजाम किये गये हैं। शत्रु देशों को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई सहित कई लोगों की मौत हुई। चलते इजरायल की संसद (नेस्सट) की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, जिसे बाद में फिर शुरू किया गया। मौजूदा घटनाक्रम को संघर्ष के सबसे तीव्र चरणों में से एक माना जा रहा है, जहां एक ओर सैन्य कार्रवाई जारी है, वहीं कूटनीतिक संकेत अभी भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

रूस ने यूक्रेन पर रातभर में 400 ड्रोन दागे, चार की मौत



कीवा। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 27 लोग घायल हुए। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक, रूस ने रातभर में करीब 400 ड्रोन दागे, जो हाल के हफ्तों के सबसे बड़े हमलों में से एक है। इसके अलावा 23 क्रूज मिसाइल और 7 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं, जिससे देश के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। राजधानी कीव पर दिन में भी ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सान्द्र सिरस्की ने कहा कि रूस कई मोर्चों पर एक साथ हमला कर रहा है और नई सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। करीब 1250 किलोमीटर लंबी सीमा पर लड़ाई जारी है। रूस पहले ही यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। वहीं, यूक्रेन भी ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है और अपने सहयोगी देशों से

ऑस्ट्रेलिया-ईयू के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता

कैनबरा। ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) ने लगभग आठ वर्षों की बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई किसानों को वाइन, डेयरी, सीफूड, अनाज, फल और नट्स जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने से लाभ होगा, जिसमें अकेले वाइन निर्यातकों को सालाना लगभग '3.7 करोड़ डॉलर' का लाभ होने की उम्मीद है। यह समझौता बीफ, भेड़ के मांस, चीनी और डेयरी जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए विस्तारित करों के माध्यम से 'साथक पहचान' सुनिश्चित करेगा।

अमेरिका ने अपने नागरिकों से जल्द से जल्द इराक छोड़ने को कहा

बगदाद। इराक में अमेरिकी दूतावास ने एक नया परामर्श जारी कर अमेरिकी नागरिकों से तुरंत इराक छोड़ने का आग्रह किया है। इस परामर्श में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों से बढ़ते खतरों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निरंतर जोखिमों का हवाला दिया गया है। एक अद्यतन नोटिस में, दूतावास ने कहा कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र सहित पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और 'हितों' को निशाना बनाते हुए व्यापक हमले किए हैं। अमेरिका ने 'यात्रा न करने' संबंधी अपनी लेवल चार की चेतावनी को दोहराते हुए सलाह दी है कि किसी भी कारण से इराक की यात्रा न करें। यदि आप वहां हैं तो अभी निकल जाएं।

पाकिस्तान बना दुनिया का सबसे प्रदूषित देश

इस्लामाबाद/नई दिल्ली। लोनी को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक होने का तमगा मिला है। एक ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान को 2025 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बताया गया है। मंगलवार को स्विस कंपनी IQAir की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में पीएम2.5 नाम के पार्टिकुलेट मैटर का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सुझाए गए स्तर से 13 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। ये कण जलने की प्रक्रियाओं, औद्योगिक प्रक्रियाओं और धूल से आते हैं और इनसे सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन 143 देशों और क्षेत्रों की निगरानी की गई है उनमें से 130 देश डब्ल्यूएचओ के मानकों को पूरा करने में नाकाम

भारत का लोनी सबसे प्रदूषित शहर रहा



रहे। इस सूची में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। शहरों की बात करे तो 2025 में भारत का लोनी शहर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा जहां पीएम2.5 का औसत स्तर 11.5 माइक्रोग्राम था। इसके बाद चीन के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र का होटान शहर रहा जहां यह स्तर 109.6 माइक्रोग्राम था।

है। इसकी एक वजह कनाडा के जंगलों में लगी आग थी जिससे पूरे अमेरिका और यहां तक कि यूरोप तक में पीएम2.5 का स्तर बढ़ गया था। 2025 में सिर्फ 13 देश ही पीएम2.5 के औसत स्तर को 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम रखने के स्टैंडर्ड को पूरा कर पाए जबकि 2024 में ऐसे देशों की संख्या सात थी। जिन देशों ने इस स्टैंडर्ड को पूरा किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा शामिल हैं। IQAir के मुताबिक 2025 में लगभग 75 देशों में पीएम2.5 का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम रहा जबकि 5.4 देशों में यह स्तर ज्यादा दर्ज किया गया। इस साल का डेटा 2024 के मुकाबले काफी कम है क्योंकि अमेरिका ने बजट की कमी का हवाला देते हुए एक वैश्विक निगरानी कार्यक्रम को बंद कर दिया था।

ईरान के राष्ट्रपति व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत

नई दिल्ली। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को फोन पर बातचीत पश्चिमी एशिया के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत 23 मार्च को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री इशाक डार और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराधवी के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री ने क्षेत्र और उससे बाहर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संवाद और कूटनीतिक महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्ष बदलती स्थिति पर निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। मंगलवार को आई खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान खुद को दोनों युद्धरत पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इस्लामाबाद में बातचीत की मेजबानी करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि इन रिपोर्टों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की महत्वपूर्ण एजेंसी (एमएनए) ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति पेजेशकियान और शहबाज शरीफ ने द्विपक्षीय संघर्ष, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और अमेरिका तथा इजरायल द्वारा किए गए अवैध हमलों के क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की।



रष्ट्रपति ने कहा कि सेना के लिए नए हेलिकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान और एंटी-ड्रोन सिस्टम तुरंत खरीदे जाने चाहिए, ताकि जवानों की सुरक्षा तय की जा सके। हादसे के बाद आसपास के गांवों के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। कई लोग मोटरसाइकिल से घायलों को अस्पताल ले गए और आग बुझाने की कोशिश की। घायलों को पहले छोटे क्लीनिक में भर्ती किया गया, फिर उन्हें बड़े शहरों जैसे बोगोटा के अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया। रक्षा मंत्री पेद्रो सांचेज

ने साफ किया है कि अभी तक किसी आतंकी या हमले के सबूत नहीं मिले हैं। यानी फिलहाल इसे एक हादसा ही माना जा रहा है। हादसे के बाद आग से विमान में मौजूद गोला-बारूद फटने लगा, जिससे हालात और खतरनाक हो गए। एक एविएशन एक्सपर्ट ने बताया कि यह विमान 2020 में अमेरिका ने कोलंबिया को दिया था और कुछ साल पहले इसका पूरा मॉटेनंस (ओवरहाल) भी किया गया था। इसलिए पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि खराब पाटर्स की वजह से हादसा हुआ। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि टेकऑफ के तुरंत बाद विमान के इंजन क्यों फेल हो गए। सी-130 हर्क्यूलस दुनिया के सबसे भारोसेमंद सैन्य परिवहन विमानों में से एक है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और बाह्य सामग्री को पहुंचाने के लिए किया जाता है।

यौन समस्याएं
यौन समस्याओं के विशेषज्ञ
 पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें
डा. सम्राट
 नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल, अप्फीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।
नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)
M-9412211108